महंगाई का भस्मासुर

सामयिक

प्रभात कुमार राय

भारत की अर्थव्यवस्था अब सटोरियों और बिचौलियों के हाथों में ही खेल रही है। किसानों की कमर तो कर्ज से झुक चुकी है। रिटेल बाजार में खाद्य पदार्थों के दाम चाहे कुछ भी क्यों न बढ़ जाएं, किसान वर्ग को इसका फायदा कभी नहीं पंहुचता। किसानों के विषय में ब्रिटिश राज की नीति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया।

डीजल और रसोई गैस के दामों में इजाफा, यकीनन पहले से सुलग रही महंगाई की भस्मासुर अग्नि को और अधिक तेज करने में सहयोग करेगा। पैट्रोलियम कंपनियों के कथित नुकसान की भरपाई करने के नाम पर पहले पेट्रोल के दाम में और अब डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोत्तरी की गई। ऑयल कंपनियों के आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। विगत वर्ष ओएनजीसी ने तकरीबन 20 हजार करोड़, इंडियन आयल ने तीन हजार करोड़ और जीएआईएल ने 3 हजार करोड़ रुपयों का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। भारत के प्रधानमंत्री को एक बेहद काबिल अर्थशास्त्री करार दिया जाता है। क्या फायदा है प्रधानमंत्री की ऐसी काबलियत का, जो आम भारतीय की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करने के बजाय उसमें बढ़ोतरी अंजाम देती रही। एक ऐसी अर्थनीति के निर्माता प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो एकदम ही अमीर कॉरपोरेट सैक्टर को फायदा पंहुचाने की गरज से तशकील की गई है। इस अर्थनीति के चलते हुए तहत आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो चली है। विगत दो वर्षों से जारी मंहगाई की दर ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अमीर आदमी को महंगाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किंतु एक गरीब इंसान की क्या बदतर हालत हो चली है, इसका कुछ भी अंदाजा शासक वर्ग को संभवतयाः नहीं है, अन्यथा इस सवाल पर इतना बेरहम रूख हुकूमत की ओर से अख्तियार नहीं किया जाता।

विपक्ष के बिखराव और खराब सियासी हालात ने कमरतोड़ महंगाई के प्रश्न पर जनमानस के रोष की अभिव्यिक्त को अत्यंत असहज कर दिया है। अन्यथा आम आदमी के अंतःस्थल में जबरदस्त ज्वालामुखी धधक रहा है। अमीर तबके के और अधिक अमीर हो जाने की की अंतहीन लिप्सा की खातिर आम आदमी को निचोड़ा जा रहा है। पैट्रोलियम मूल्यों को बेलगाम कर दिया गया है। ये ऐसा हो रहा कि हकूमत द्वारा महंगाई के दावानल में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस को भी डाल दिया गया। महंगाई के प्रश्न पर आम आदमी का रोष इसलिए भी राजनीतिक जोर नहीं पकड़ रहा, क्योंकि प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का अपना चरित्र भी अमीर कॉरपोरेट परस्त होता जा रहा है। संसद के सदस्य अपना वेतन अब बीस हजार से बढ़ाक र नब्बे हजार करने जा रहे हैं, जोकि हुकूमत के सचिव रैंक के अफसर के वेतन के समकक्ष होगा।

सरकारी आंकड़े खुद ही बयान करते हैं कि विगत वर्ष के दौरान खाने पीने की वस्तुओं के दाम 16.5 की इंफलेशन दर से बढ़े हैं। चीनी के दाम 73, मूंग की दाल के दाम 113 , उड़द की दाल के दाम 71, अनाज के दाम 20 और अरहर की दाल के दाम 58 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। रिटेल के दामों और थोक दामों में भारी अंतर बना ही रहता है। सरकारी आंकड़े महज थोक सूचकांक बताते हैं, जबकि आम आदमी तक पहुंचते-पहुंचते बहुत से बिचौलियों और दलालों की जेबें गरम जो चुकी होती हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था अब सटोरियों और बिचौलियों के हाथों में ही खेल रही है। अपना खून पसीना एक करके उत्पादन करने वाले किसानों की कमर तो कर्ज से झुक चुकी है। रिटेल बाजार में खाद्य पदार्थों के दाम चाहे कुछ भी क्यों न बढ़ जाएं, किसान वर्ग को इसका फायदा कभी नहीं पंहुचता। आजाद हिंदुस्तान में किसानों के विषय में ब्रिटिश राज की नीति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। देश का 80 करोड़ किसान शासकीय नीति में बाकायदा उपेक्षित है। विगत दो वर्षों के दौरान देश का किसान और अधिक गरीब हुआ है, जबकि उसके द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों के दामों में भारी इजाफा दर्ज किया गया। यह समूचा मुनाफा अमीरों की जेबों में चला गया। देश के अमीरों की अमीरी ने अद्भुत तेजी के साथ कुलांचे भरीं। मंत्रियों और प्रशासकों के वेतन में जबरदस्त वृद्धि हो गई। दूसरी ओर साधारण किसानों में गरीबी का आलम है। आम आदमी की रोटी-दाल किसानों ने नहीं, वरन बड़ी तिजोरियों के मालिकों ने दूभर कर दी है।

वस्तुतः समस्त देश में आर्थिक सामाजिक हालात में सुधार का नाम ही वास्तविक विकास है। एक वर्ग के अमीर बनते चले जाने और किसान मजदूरों के दरिद्र बनते जाने का नाम विकास नहीं, बल्कि देश का विनाश है। निरंतर गति से बढ़ती हुई महंगाई और शोषण का चोली दामन का साथ है। महंगाई वास्तव में ताकतवर अमीरों द्वारा गरीबों को लूटने का एक अस्त्र है। इस खतरनाक साजिश में सरकारें भी अमीरों के साथ बाकायदा शामिल हैं। वास्तव में सरकार ने बाजार की ताकतों को इतना प्रश्रय प्रदान कर दिया है कि घरेलू बाजार व्यवस्था नियत्रंण से बाहर होकर बेकाबू हो चुकी है। सटौरिये, दलाल और बिचौलिये इसमें सबसे अहम किरदार हो गए हैं। देश में दुग्ध उत्पादन की कमी है, किंतु केसिन चीज और मिल्क पाउडर का निर्यात बदस्तूर जारी है। देश का जनमानस कृषि उत्पादों की महंगाई से बेहद त्रस्त है, किंतु कृषि उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। दो साल से सरकार दावा करती आ रही है कि मूल्य वृद्धि पर काबू पा लिया जाएगा, किंतु नतीजा एकदम सिफर रहा। अधिक मांग का दबाब न होने एवं फसलों के भरपूर होने बावजूद कीमतों की उड़ान क्यों जारी रही है, सरकार इस सवाल पर कन्नी काटती नजर आती है। वायदा बाजार बाकायदा फल-फूल रहा है। काले बाजार और काले अघोषित गोदामों में किसान के चावल, चीनी, दाल और गेंहू आदि के जखीरे को दबाकर बाजार में चालू आपूर्ति को कम कर दिया गया। कुछ अनचाहे अधमने सरकारी छापों में ही गोदामों में बाकायदा दबा पड़ा विशाल भंडार दिखाई दे गया। राजकाज और बाजार की मिली भगत ने अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि राज्य व्यवस्था और बाजार के मध्य फर्क महज औपचारिकता बन कर रह गया है। काली राजनीति का काले धंधे के साथ अवैध समीकरण भारत की जम्हूरियत और राज व्यवस्था का खास चेहरा बन गए हैं। वर्तमान राजनीतिक समीकरण ने संभवतयाः शासक वर्ग को कुछ अधिक ही आश्वस्त कर दिया कि उनकी सत्ता को आम आदमी के रोष से निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है, किंतु वे ऐतिहासिक सच्चाई को विस्मृत कर चुके हैं। इस संदर्भ में ये पंक्तियां स्मरण हो आती हैं-

कबीरा हाय गरीब की कबहु न खाली जाए।
मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए।।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission